

UPSC Daily Current Affairs 22 Jun 2021

1. जूनटीथ: नई संघीय छुट्टी

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I- विश्व इतिहास, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में क्यों है?

- हाल में, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक कानून पर हस्ताक्षर करने की संभावना है जिसके द्वारा जून 19 अथवा जूनटीथ, एक राष्ट्रीय छुट्टी के रूप में संघीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कर लेगा। यह दिन अमेरिकी गृहयुद्ध (1861-65) के बाद गुलामी के अंत की याद में मनाया जाता है।

खबरों में और भी है

- जूनटीथ लगभग चार दशकों में पहली बार सृजित किए जाने वाला पहली नई संघीय छुट्टी होगी, और इसे वर्तमान की 10 वार्षिक छुट्टियों की तरह से ही दर्जा हासिल होगा, जिसमें मेमोरियल दिवस, वेटेरन्स दिवस और थैंक्सगिविंग दिवस शामिल हैं।
- अंतिम ऐसी छुट्टी- मार्टिन लूथर किंग जू. दिवस की घोषणा 1983 में की गई थी, जो नागरिक अधिकार नायक के सम्मान में थी।

जूनटीथ के बारे में जानकारी

- जूनटीथ- जून की प्रतिकृति और नाइनटीथ- US में गुलामी प्रथा की समाप्ति का सबसे पुराना राष्ट्रीय समारोह है, यह प्रत्येक वर्ष जून 19 को मनाया जाता है।
- वर्तमान में, इसे 47 US राज्यों और कोलम्बिया जिले में छुट्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- इसे मुक्ति दिवस अथवा जीनटीथ स्वतंत्रता दिवस भी कहा जाता है।

पृष्ठभूमि

- 1 जनवरी, 1863 को, तत्कालीन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने एक **मुक्ति घोषणा** को जारी किया, जिसने घोषित किया कि जितने भी लोग विद्रोह वाले राज्यों में गुलामों के रूप में बंधक हैं, अबसे मुक्त होंगे।
- इतना होने के बावजूद लिंकन की घोषणा के दो वर्षों के बाद भी, कई गुलामों के स्वामियों ने अपने गुलामों को बंधक बनाये रखा और इसके लिए उनसे यह सूचना छिपाकर रखी और एक फसल मौसम के लिए उन्हें अपने पास रखा। यह कांग्रेसनल अनुसंधान सेवा (CRS) के अनुसार है।

जूनटीथ का महत्व

- 19 जून, 1865 को, मेजर जनरल गॉर्डन ग्रेन्गर गैल्वेस्टन में पहुंचे और गृहयुद्ध और गुलामी दोनों के अंत की घोषणा की।
- तब से, जूनर्टीथ एक बड़ी सांकेतिक तिथि बन गई है जो अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करती है।

2. म्यांमार की सू की ने फूल विरोध प्रदर्शनों के लिए समर्थकों को धन्यवाद दिया

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- IR, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में क्यों है?

- हाल में, अपदस्थ म्यांमार की नेता आंग सान सू की ने फूल विरोध प्रदर्शनों के साथ अपने 76वें जन्मदिन को मनाकर जुंता का विरोध करने के लिए अपने समर्थकों का धन्यवाद दिया। उनके खिलाफ कई आपराधिक मामलों में मुकदमें शुरू हो गए हैं।

खबरों में और भी है



- पूरे देश में प्रदर्शनकारियों ने अपने बालों में फूल लगाए- यह सू की पुराना तरीका है- जिससे लोकतंत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति के जन्मदिन को मनाया जा सके, जो जुंता द्वारा घर में नजरबंदी के दौरान 76 वर्ष की हो गई हैं।
- कई लोगों ने फूलों वाली बालों की शैली की नकल की और सोशल मीडिया पर अपने चित्र अपलोड किए।

MYANMAR MILITARY BACK IN POWER: TIMELINE OF EVENTS



*Myanmar has a constitutional arrangement for 25% of parliament seats to be reserved for the military
Infographic by Rafa Estrada



- 1 फरवरी 2021 से जबसे सेना ने सत्ता पर कब्जा किया है पूरे म्यांमार में जन प्रदर्शन हो रहे हैं।
- म्यांमार की सेना ने तख्ता पलट के द्वारा सत्ता पर कब्जा कर लिया था- यह 1948 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के बाद देश के इतिहास में तीसरी बार है।

सैन्य तख्ता पलट के बारे में जानकारी

- नवंबर 2020 के संसदीय चुनाव में, सू की की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (NLD) ने बहुमत प्राप्त किया था।
- म्यांमार की संसद में, 2008 के सेना द्वारा संविधान के तैयार प्रारूप के अनुसार सेना को कुल सीट की 25% सीटें हासिल हैं और सेना द्वारा नियुक्त किए गए कई लोगों के लिए भी कई प्रमुख मंत्रालय आरक्षित हैं।

- जब 2021 में संसद के पहले सत्र का आयोजन म्यांमार के नए चुने हुए संसद सदस्यों द्वारा किया जाना था, सेना ने एक वर्ष के लिए आपातकाल लगा दिया जिसके लिए उन्होंने संसदीय चुनावों में जबर्दस्त मतदान धांधली का आरोप लगाया था।

अब कौन सत्ता में है?

- सैन्य कमांडर प्रमुख **मिन आंग हलेंग** का सत्ता पर कब्जा है।
- लंबे समय से उनका राजनीतिक प्रभाव है, उन्होंने सफलतापूर्वक टाटमाडा- म्यांमार की सेना का कब्जा बनाए रखा है- जबकि देश लोकतंत्र की ओर जा चुका था।
- उन्हें जातीय अल्पसंख्यकों पर सेना के हमलों की अपनी तथाकथित भूमिका के लिए कई अंतरराष्ट्रीय आलोचनाओं और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है।
- तख्ता पलट के बाद अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणियों में जनरल हलेंग ने सत्ता पर कब्जे को न्यायोचित ठहराना का प्रयास किया।
- उन्होंने कहा कि सेना जनता की तरफ है और एक सही और अनुशासित लोकतंत्र की स्थापना करेगी।
- सेना का कहना है कि एक बार आपातकाल समाप्त हो जाए तो वह मुक्त और निष्पक्ष चुनाव करवाएगी।

लोगों ने कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त की?

- तख्ता पलट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन 2007 के तथाकथित सैफरन क्रांति के बाद से सबसे बड़े हैं, जब हजारों भिक्षु सैनिक शासन के खिलाफ उठ खड़े हुए थे।
- प्रदर्शनकारियों में शिक्षक, वकील, छात्र, बैंक अधिकारी और सरकारी कर्मचारी शामिल हैं।
- सेना ने प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें कर्फ्यू और इकट्ठा होने पर सीमाएं शामिल हैं।

आंग सान सू की कौन हैं?

- आंग सान सू की 1990 के दशक में विश्व प्रसिद्धि उस समय हुई जब उन्होंने लोकतंत्र की पुनर्बहाली के लिए अभियान चलाया था।
- उन्होंने लोकतांत्रिक सुधार और मुक्त चुनावों का आह्वान करने के लिए रैलियों का आयोजन किया जिसकी वजह से 1989 से 2010 के मध्य लगभग 15 वर्षों तक जेल में बिताए।
- घर में नजरबंदी के दौरान 1991 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- 2015 में, उन्होंने 25 वर्षों में म्यांमार में पहली बार हुए खुले चुनाव में NLD को जीत दिलवाई।

3. रईसी नाभिकीय बातचीत के तैयार, बाइडेन के साथ भेंट से इंकार किया

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- IR, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में क्यों है?

- ईरान के निर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने हाल में कहा कि वे केवल बातचीत के लिए नाभिकीय बातचीत (JCPOA) की अनुमति नहीं देंगे।

खबरों में और भी है

- रईसी ने US के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने से भी इंकार कर दिया लेकिन कहा कि शिया ईरान के सुन्नी शासित क्षेत्रीय विरोधी सऊदी अरब के साथ कूटनीतिक संबंधों को फिर से शुरू करने में कोई बाधा नहीं है।

विएना बातचीत

- विएना में, बाइडेन ने समझौते पर वापस लौटने का संकेत दिया और विभिन्न पक्ष जिनमें ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, जर्मनी और रूस शामिल हैं- हाल में विएना में इसके पुनर्जीवन के लिए बातचीत कर रहे हैं।

ईरान का नाभिकीय समझौता

पृष्ठभूमि

- ईरान पूरी तरह से JCPOA (संयुक्त समग्र कार्ययोजना) नाभिकीय समझौते से बाहर हो चुका है। यह घोषणा उस समय की गई जब US सेनाओं ने **जनरल कासेम सोलेमानी** की हत्या कर दी।

ईरान नाभिकीय समझौते के बारे में जानकारी

- ईरान नाभिकीय समझौते (अथवा संयुक्त समग्र कार्ययोजना (JCPOA) पर ईरान और पी5 प्लस जर्मनी और यूरोपीय संघ के बीच में 2015 में हस्ताक्षर किए गए थे।
- पी5 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (US, चीन, फ्रांस, रूस और UK) के पांच स्थाई सदस्य हैं।
- इस समझौते का लक्ष्य ईरान के नाभिकीय कार्यक्रम को रोकना है।

समझौते के अंतर्गत:

- ईरान का अधिकांश प्रसंस्कृत यूरेनियम देश के बाहर भेज दिया गया।
- एक भारी जल सुविधा को निष्क्रिय कर दिया गया।
- संचालित होने वाली नाभिकीय सुविधाओं को अंतरराष्ट्रीय जांच के अंतर्गत लाया गया।
- इसके बदले में, समझौते में ईरान पर से अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाना शामिल था।

US क्यों समझौते से बाहर निकला?

- ट्रंप और समझौते के विरोधियों का कहना है कि यह असंतुलित है क्योंकि यह ईरान को अरब डॉलरों तक की पहुँच को सुनिश्चित करती है लेकिन हमास और हिजबुल्लाह जैसे समूहों को जिन्हें US आतंकवादी मानता है, को ईरान के समर्थन की समस्या को नहीं सुलझाता है।
- इसका कहना है कि यह समझौता ईरान द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास को नहीं रोकता है और यह समझौता 2030 तक समाप्त हो जाएगा।
- उनका कहना है कि पूर्व में ईरान ने अपने नाभिकीय कार्यक्रम के बारे में झूठ बोला है।

4. अजीत मिश्रा समिति

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन, स्रोत- PIB)

खबरों में क्यों है?

- हाल में, सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि प्रेस के कुछ वर्ग और हितधारकों का यह विचार है कि न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय मजदूरी निम्न सीमा को निर्धारित करने के लिए समिति को उपलब्ध कराए गए तीन वर्ष इस प्रक्रिया में देरी करने का प्रयास है।

अजीत मिश्रा समिति के बारे में जानकारी

- केंद्र सरकार ने प्रोफेसर अजीत मिश्रा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है।
- इस समिति का गठन सरकार को न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय मजदूरी निम्न सीमा के निर्धारण पर तकनीकी इनपुट्स और संस्तुतियां देने के लिए किया गया।

कार्यकाल

- इस विशेषज्ञ समूह का कार्यकाल तीन वर्ष है।

कार्यकाल क्यों तीन वर्ष का है?

- सरकार ने कहा कि विशेषज्ञ समूह का कार्यकाल इसलिए तीन वर्ष रखा गया है जिससे न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय मजदूरी निम्न सीमा के निर्धारण के बाद भी, सरकार जब भी जरूरत हो न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय मजदूरी निम्न सीमा से संबंधित विषयों पर विशेषज्ञ समूह से तकनीकी इनपुट्स/सलाह ले सके।

5. आत्महत्या को गैर-अपराधी बनाने के लिए मामला

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- सामाजिक मुद्दे, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में क्यों है?

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दक्षिणपूर्व एशियाई क्षेत्र में सबसे ज्यादा आत्महत्या दर भारत में है।

आत्महत्या के कारण

- अवसाद, असाध्य खराब स्वास्थ्य, गलती की भावना, अभिघात, मादक पदार्थों का प्रयोग, परीक्षाओं में असफलता और प्रिय लोगों की मृत्यु कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से लोग अपने जीवन को खत्म करने का निर्णय लेते हैं।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, भारत में 2018 में कुल 1,34,516 आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए।
- 2017 में जहां आत्महत्या की दर 9.9 थी, वहीं 2018 में यह 10.2 हो गई।

अपराध और दंड

अनुच्छेद 309 के बारे में जानकारी

- भारतीय दंड संहिता का अनुच्छेद 309 आत्महत्या का प्रयास करने वालों के लिए दंड का प्रावधान प्रदान करता है।
- यदि कोई व्यक्ति किसी मानसिक अभिघात अथवा बीमारी से पीड़ित है, इसे सुधारात्मक उपचार देने की जरूरत है ना कि निवारक दंड देने की जरूरत है जो कि एक अवधि के लिए सामान्य कारावास है जो एक वर्ष (अथवा अर्धदंड के साथ अथवा दोनों एक साथ हो सकते हैं) तक बढ़ सकता है।
- यह औपनिवेशिककालीन कानूनी अनुच्छेद है जिससे तथ्यता भारत में गैर-आपराधिक नहीं घोषित किया गया है लेकिन ब्रिटिश संसद ने आत्महत्या कानून के द्वारा 1961 में आत्महत्या के प्रयास को गैर-आपराधिक घोषित कर दिया था।

आत्महत्या के दंडात्मक प्रावधान के पक्ष में निर्णय

- जो दंडात्मक प्रावधान का समर्थन करते हैं वे अक्सर **ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य (1996)** में निर्णय को उद्धृत करते हैं जहां न्यायालय ने कहा था कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में सम्मिलित एक प्राकृतिक अधिकार है लेकिन आत्महत्या जीवन की अप्राकृतिक तरीके से समाप्ति है, इसलिए, जीवन के अधिकार की संकल्पना के साथ असंगत है।
- **अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत सरकार (2011)** मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व के निर्णय को सही ठहराया था।

अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन

- चिन्ना जगदीश्वर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और पी. रथीनम बनाम भारत सरकार (1994) के मामले में जहां न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारतीय दंड संहिता का अनुच्छेद 309 अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है और शून्य एवं गैरसंवैधानिक है।

संबंधित सूचना

इच्छामृत्यु के बारे में जानकारी

- इसे दया मृत्यु भी कहा जाता है जो दर्दनाक और असाध्य रोग अथवा अशक्त कर देने वाले भौतिक विकार से ग्रस्त व्यक्ति को मृत्यु प्रदान करता है। साथ ही इसमें उपचार रोककर अथवा कृत्रिम जीवन समर्थन देने वाले उपार्यों को हटाकर भी उन्हें मरने की अनुमति दी जाती है।
- क्योंकि अधिकांश कानूनी प्रणालियों में इसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है, इसे सामान्य तौर पर या तो आत्महत्या (यदि रोगी द्वारा स्वयं किया जाता है) अथवा हत्या (किसी अन्य द्वारा किये जाने पर) माना जाता है।
- अरुणा शानबाग बनाम भारत सरकार के मामले में, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सक्रिय और निष्क्रिय इच्छामृत्यु के बीच में स्पष्ट अंतर किया है।
 - निष्क्रिय इच्छामृत्यु का अर्थ है प्राकृतिक तरीके से मृत्यु को प्रेरित करने के लिए जीवन समर्थन को हटाना।
 - सक्रिय इच्छामृत्यु का अर्थ है मृत्यु को प्रेरित करने के लिए कानूनी औषधियों को सुई द्वारा शरीर में प्रवेश कराना।

नोट:

- जीवन का अधिकार को संविधान की मूल विशेषता के रूप में देखा जाता है, इसलिए यह मूलभूत और स्थाई दोनों ही है।

6. एकीकृत विद्युत विकास योजना

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- पर्यावरण, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में क्यों है?

- हाल में 'आजादी का अमृत महोत्सव' के भाग के रूप में, एकीकृत विद्युत विकास योजना के अंतर्गत सोलन, हिमाचल प्रदेश में एक 50 kWp के सौर छत का उद्घाटन किया गया।

एकीकृत विद्युत विकास योजना के बारे में जानकारी

- इसकी शुरुआत 3 दिसंबर 2014 को की गई।
- यह विद्युत मंत्रालय की फ्लैगशिप योजना है।

नोडल एजेंसी

- विद्युत वित्त निगम (PFC) MoP के संपूर्ण दिशा-निर्देश के अंतर्गत योजना के क्रियान्वयन और संचालन के लिए नोडल एजेंसी है।

घटक

- शहरी क्षेत्रों में उप-संप्रेषण और वितरण नेटवर्कों को मजबूत करना।
- शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग।
- वितरण क्षेत्र की IT सक्षमता और 12वीं और 13वीं योजना के लिए R-APDRP के अंतर्गत वितरण नेटवर्क को मजबूत करना। इसके लिए R-APDRP से IPDS के लिए स्वीकृत आवंटन को आगे ले जाया जाएगा।
- उद्यम संसाधन योजना (ERP) के लिए योजनाएं और बचे हुए शहरी शहरों का IT सक्षमीकरण। इसे भी IPDS के अंतर्गत शामिल किया गया है। IT सक्षमीकरण का दायरा 2011 की जनगणना के अनुसार सभी 4041 शहरों में बढ़ाया गया है।
- राज्यों की अतिरिक्त मांग को शामिल करने के लिए भूमिगत केबलिंग और योजना के अंतर्गत UDAY राज्यों को प्रदर्शित करने के लिए स्मार्ट मीटरिंग हल और सरकारी भवनों पर सौर पैनलों के साथ नेट मीटरिंग को भी योजना के तहत अनुमति दी गई है।

योजना के वृहद् उद्देश्य

- उपभोक्ताओं के लिए 24x7 विद्युत आपूर्ति।
- राज्यों के साथ सलाह से MoP द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित पथ के रूप में AT&C हानियों में कटौती।
- सभी परिवारों को विद्युत देने के लिए पहुँच उपलब्ध करवाना।

संबंधित सूचना

‘गो ग्रीन’ पहल के बारे में जानकारी

- यह परियोजना सरकार की पहल ‘गो ग्रीन’ को फिर से पुनर्स्थापित करता है जैसा कि भारत सरकार की शहरी वितरण योजना में संकल्पना की गई है।
- वर्तमान में चल रही छत सौर के रूप में ‘गो ग्रीन’ पहल के अंतर्गत, सौर पैनलों को उत्तर प्रदेश (100 मेगावाट), कर्नाटक (8 मेगावाट), केरल (5 मेगावाट), पश्चिम बंगाल (4 मेगावाट), उत्तराखंड (3 मेगावाट) और हिमाचल प्रदेश (1 मेगावाट) में भी संस्थापित किया गया है।

[7. भारतीय चिकित्सा उपकरण प्रमाणन \(ICMED\) 13485 प्लस योजना](#)

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- स्वास्थ्य, स्रोत- AIR)

खबरों में क्यों है?

- हाल में, भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) और भारतीय चिकित्सा उपकरण विनिर्माणकर्ता संघ (AiMeD) ने भारतीय चिकित्सा उपकरण प्रमाणन (ICMED) 13485 प्लस योजना की शुरुआत की है।

भारतीय चिकित्सा उपकरण प्रमाणन (ICMED) प्लस योजना के बारे में जानकारी

- ICMED 13485 PLUS, जैसा कि नई योजना का नामकरण किया गया है, चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता, सुरक्षा और सामर्थ्य के प्रमाणन को करेगी।
- ICMED 13485 Plus को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि परिभाषित उत्पाद मानकों और विशिष्टीकरण के संदर्भ के साथ उत्पादों के विटनेस परीक्षण के द्वारा गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली घटक और उत्पाद संबंधित गुणवत्ता वैधता प्रक्रियाओं को एकीकृत किया जा सके।

महत्व

- यह दुनिया में पहली योजना है जिसमें गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियां साथ में उत्पाद प्रमाणन मानकों को विनियमन जरूरतों के साथ एकीकृत किया गया है।
- यह योजना भारत में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के लिए शुरू से अंत तक गुणवत्ता आश्वासन योजना होगी।
- यह योजना उत्पाद गुणवत्ता और सुरक्षा के आश्वासन के लिए अत्यंत जरूरी संस्थागत तंत्र को उपलब्ध कराती है।
- यह खराब मानक के चिकित्सा उत्पादों अथवा उपकरणों जो संदेहास्पद हैं एवं स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हैं, उनके चक्रण और प्रयोग के उन्मूलन में मदद करेगी।

पृष्ठभूमि

भारतीय चिकित्सा उपकरण प्रमाणन योजना के बारे में जानकारी

- इस योजना की शुरुआत 2016 में भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग (AIMED) ने भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) एवं राष्ट्रीय प्रमाणन निकायों के लिए प्रत्यायन बोर्ड (NABCB) के साथ मिलकर चिकित्सा उपकरणों के प्रमाणन के लिए किया था।

उद्देश्य

- देश में चिकित्सा उपकरणों के लिए गुणवत्ता प्रमाणन क्षेत्र में विनियमन शून्य को भरना।

इस योजना की शुरुआत प्रमाणन के दो स्तरों के साथ की गई है-

- a. ICMED 9000 प्रमाणन जो ISO 9001 प्लस अतिरिक्त जरूरतें है।

b. ICMED 13485 जो ISO 13485 प्लस अतिरिक्त जरूरतें है।

भारतीय गुणवत्ता परिषद के बारे में जानकारी

- भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) का गठन 1997 में किया गया था।
- यह एक स्वायत्त निकाय है जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग से जुड़ा है।
- QCI के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा सरकार से उद्योग की संस्तुति से की जाती है।

QCI के प्रत्यायन बोर्ड

- प्रमाणन निकायों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NABCB) और परीक्षण एवं कैलीब्रेशन प्रयोगशालाओं के लिए प्रत्यायन बोर्ड (NABL) QCI के दो प्रत्यायन बोर्ड हैं।
- ये दो निकाय आपस में करीब से काम करते हैं जिससे सरकार और विनियामकों को यह सुनिश्चित करवाया जा सके कि प्रत्यायित अनुरूपता आकलन निकायों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े मजबूत, विश्वसनीय, निर्णय लेने, अनुपालन और मानक निर्धारण के संदर्भ में विश्वास योग्य हैं।
- QCI में भारतीय उद्योग का प्रतिनिधित्व तीन प्रमुख उद्योग संघों- भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (ASSOCHAM), भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ (FICCI) द्वारा किया जाता है।

8. विद्युत मंत्रालय ने संप्रेषण शुल्कों में छूट के लिए RE के लिए समयरेखा को 2 वर्षों के लिए बढ़ाया

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- पर्यावरण, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में और भी है?

- हाल में, विद्युत मंत्रालय ने 30 जून 2025 तक लगने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन स्रोतों से उत्पन्न विद्युत के संप्रेषण पर अंतर-राज्यीय संप्रेषण प्रणाली (ISTS) शुल्कों की छूट को बढ़ाने के लिए एक आदेश जारी किया है।
- पूर्व में, यह 30 जून, 2023 तक ही लागू था।

इस कदम का महत्व

- यह सौर, पवन, जल द्वारा पंप किए गए भंडारण संयंत्र और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, विद्युत विनिमय में नवीकृत ऊर्जा के व्यापार, और पूरे राज्यों में नवीकृत ऊर्जा विद्युत के बाधारहित संप्रेषण के विकास को प्रोत्साहित करने में मदद देगा।

- यह विद्युत ग्रिड में अर्थात् 2030 तक लगभग 450 गीगावाट नवीकृत के बड़े पैमाने पर एकीकरण की वजह से पैदा हुई ग्रिड की बाकी जरूरतों को पूरा करने के लिए जल से पंप किए गए भंडारण संयंत्र और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजनाओं को प्रोत्साहित करेगी।
- संप्रेषण शुल्कों में छूट को दो वर्षों के लिए अर्थात् 30 जून 2023 तक ग्रीन टर्म अहेड बाजार (GTAM) और ग्रीन डे अहेड बाजार (GDAM) में सौर, पवन, PSP और BESS से उत्पादित/ आपूर्ति विद्युत के व्यापार के लिए अनुमति दी गई है।
- नवीकरणीय ऊर्जा के बिक्रेताओं को अपने आधिक्य विद्युत को विद्युत विनिमयों में बेचने के अवसर भी मिलेंगे अथवा उन्हें विद्युत विनिमय में बिक्रेताओं को बेचने की अग्रिम अनुमति होगी।
- यह संशोधन आदेश नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक प्रोत्साहन होगा और भारत सरकार के लिए मौसम परिवर्तन की ओर अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में एक कदम आगे बढ़ाना होगा।

9. विश्व निवेश रिपोर्ट 2021

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- अर्थशास्त्र, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में क्यों है

- UN व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD) द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 को हाल में जारी किया गया।

प्रमुख खास बातें

वैश्विक परिदृश्य

- वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश महामारी की वजह से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और वे पूर्व वर्ष के \$1.5 ट्रिलियन से गिरकर 2020 में \$1 ट्रिलियन हो गए हैं।
- पूरे विश्व में कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन से वर्तमान निवेश परियोजनाएं धीमी पड़ गई हैं और नई परियोजनाओं के पुनः आकलन के लिए बहुराष्ट्रीय उद्यमों (MNEs) के नेतृत्व में मंदी की संभावना है।
- महामारी ने वैश्विक रूप से डिजिटल अवसंरचना और सेवाओं में मांग को प्रोत्साहित किया है। इसकी वजह से ग्रीनफील्ड विदेशी प्रत्यक्ष निवेश परियोजनाओं की घोषणाओं में उच्च मूल्य प्राप्त हो रहे हैं जो ICT उद्योग को लक्षित कर रहे हैं, ये 22 प्रतिशत बढ़कर \$81 अरब तक पहुँच गए हैं।

भारत और रिपोर्ट

- FDI बार्हिप्रवाह के मामले में भारत का 20 सर्वोच्च अर्थव्यवस्थाओं में 18 स्थान है, जिसमें 2020 के दौरान देश में 12 अरब डॉलर के बार्हिप्रवाह रिकॉर्ड किए गए जबकि इसकी तुलना में यह आंकड़ा 2019 में 13 अरब डॉलर था।
- रिपोर्ट ने कहा भारत में FDI 2019 के \$51 अरब से बढ़कर 2020 में \$64 अरब तक पहुँच गया। इस वृद्धि का प्रमुख कारण सूचना और संचार तकनीक (ICT) उद्योग में अधिग्रहण रहा जिससे देश दुनिया में पांचवां सबसे बड़ा FDI प्राप्त करने वाला देश बन गया।
- देश का निर्यात संबंधित विनिर्माण, जो एक प्राथमिकता वाला निवेश क्षेत्र है, पुनर्वापसी करने में काफी समय लेगा, लेकिन सरकार का प्रोत्साहन मदद कर सकता है।
- भारत की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, जिसे प्राथमिकता उद्योग में विनिर्माण और निर्यातोनमुखी निवेश को आकर्षित करने के लिए बनाया गया है, जिसमें आटोमोटिव और इलेक्ट्रानिक्स शामिल हैं, विनिर्माण में निवेश को वापस ला सकते हैं।
- 2021 में भारत से निवेश के स्थिर होने की संभावना है, जिसे यूरोपीय संघ (EU) के साथ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) बातचीत देश द्वारा शुरू करने और अफ्रीका में मजबूत निवेश से समर्थन मिल रहा है।

UNCTAD के बारे में जानकारी

- संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (UNCTAD) की स्थापना 1964 में दुनिया की अर्थव्यवस्था में विकासशील देशों के विकास हितैषी एकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी।
- UNCTAD एक स्थाई अंतरसरकारी निकाय है जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।

इसके द्वारा प्रकाशित कुछ रिपोर्ट निम्न हैं:

- व्यापार एवं विकास रिपोर्ट
- विश्व निवेश रिपोर्ट
- अल्प विकसित देश रिपोर्ट
- सूचना और अर्थव्यवस्था रिपोर्ट
- तकनीक और नवाचार रिपोर्ट
- वस्तु एवं विकास रिपोर्ट